आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, गुरुवार 16 अप्रैल 2026

■ वर्ष : 5 ■ अंक : 145

■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2

dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

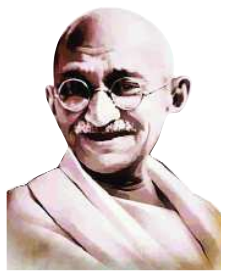

राष्ट्रपिता को नमन...

नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व, लेकिन खर्च का सवाल भी जरूरी

अक्षय की बात

अपनों के साथ

महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रयास भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर कहा जा सकता है। लंबे समय से यह मांग उठती रही कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी मिले। ऐसे में यह कदम लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल है।

इस आरक्षण से महिलाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर मिलेगा, जिससे नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। महिलाओं से जुड़े मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार पर अधिक संवेदनशील और व्यावहारिक फैसले लिए जा सकेंगे। यह न केवल महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा बल्कि समाज में समानता की भावना को भी बढ़ावा देगा।

हालांकि, इस पहल के साथ एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है जिस पर चर्चा होना आवश्यक है—और वह है इसका आर्थिक प्रभाव। संसद और विधानसभाओं में सीटों के पुनर्गठन, परिसीमन और नई व्यवस्थाओं के कारण प्रशासनिक खर्च में वृद्धि होना तय है। नई सीटों का निर्माण, संसदीय ढांचे का विस्तार, सुरक्षा और संसाधनों की व्यवस्था—इन सब पर अतिरिक्त खर्च आएगा, जिसका बोझ अंततः जनता पर ही पड़ेगा।

इसके अलावा, यदि कुल सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो जनप्रतिनिधियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं पर भी खर्च बढ़ेगा। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को संतुलित और व्यावहारिक ढंग से लागू करे, ताकि नारी सशक्तिकरण के इस प्रयास का आर्थिक बोझ आम जनता पर अत्यधिक न पड़े।

निष्कर्ष : महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना एक प्रगतिशील और स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इसके साथ आर्थिक प्रबंधन और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। यदि सरकार इस संतुलन को बनाए रखती है, तो यह पहल न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए लाभकारी साबित होगी।

कांग्रेसी नेताओं की अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● वंदे मातरम् विवाद के बाद कांग्रेस के नेताओं की अलग-अलग बयानबाजी ने पार्टी को ही बांट दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे तक - इन सभी ने अलग-अलग तरह से बयान दिए हैं। कोई साजिश की बात कर रहा है, तो कोई पार्षदों के पाकिस्तान में बसने का मुद्दा उठा रहा है। इन बयानबाजियों ने कांग्रेस को ही एक तरह से दो खेमों में बांट दिया है।

इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में आठ अप्रैल को कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम देरी से आईं। बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम् नहीं गाना था, इसलिए देरी से आईं। इस पर फौजिया ने कहा कि मैं नहीं गाऊंगी, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गाना जरूरी है। फिर पार्षद रुबीना इकबाल खान ने बोल दिया कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो जबरदस्ती वंदे मातरम् बुलवा सके।

इस मामले में फौजिया ने पुलिस को बयान दिया कि वह राष्ट्रगीत का हमेशा सम्मान करती रही हैं। पहले भी वह बैठकों में रही हैं। संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, किसी को गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वहीं रुबीना खान ने कहा कि दो शब्द गलत बोले थे, इसके लिए मैं खेद जता चुकी हूं। हमेशा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान किया है।

निगम सभापति मुन्नालाल यादव और बीजेपी पार्षद कमल वाघेला की शिकायत पर पुलिस ने पहले सभी के बयान लिए। फौजिया और रुबीना के भी बयान हुए। इसके बाद बीएनएस की धारा 196(1) और 3(5) में केस किया। इसमें 196(1) में है कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर समूहों में शत्रुता फैलाने का अपराध, माहौल खराब करना। इसमें तीन से पांच साल की सजा का प्रावधान है। वहीं 3(5) में है कि जब कोई सामूहिक रूप से अपराध करे। वहीं कांग्रेस मप्र प्रभारी महेश चौधरी ने इसमें जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। इसमें मप्र कांग्रेस के सह-प्रभारी संजय दत्त और उषा नायडू सदस्य हैं। कमेटी को सात दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ताकि संगठन स्तर पर उचित कार्रवाई की जा सके।

● ***पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह***- *यह बीजेपी की कुटिल साजिश है। दोनों महिला पार्षद देरी से आईं तो उन्हें अलग से वंदे मातरम् गाने के लिए कहा गया। यह बीजेपी का हिंदू-मुस्लिम में बांटने का प्रयास है।*

● ***प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी***- *राष्ट्रगीत नहीं गाना अपना संवैधानिक अधिकार हो सकता है, पर यह कहना कि मैं नहीं गाऊंगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पार्टी को घटना की जानकारी है और समय पर कार्रवाई होगी।*

● ***नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार***- *जब इस तरह की बात होती है तो पार्टी को समय पर कार्रवाई करना चाहिए।*

● ***शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे***- *इस मामले में उनके तीन बयान आए। विवाद वाले दिन कहा कि वंदे मातरम् हमारी रगों में है। यह उनकी (पार्षदों) व्यक्तिगत राय है। इसके साथ ही चिंटू ने कांग्रेस के सभी आयोजनों में वंदे मातरम् गान को अनिवार्य कर दिया।*

● ***दूसरा बयान दिया कि रुबीना*** *को पार्टी से निष्कासित ही मानें, कार्रवाई के लिए भोपाल पत्र लिखा है। दोनों पार्षदों पर एफआईआर के बाद तीसरा बयान आया कि सबसे पहले हमारे लिए देश है और उसकी गरिमा है। इसके ऊपर कोई चीज नहीं आती है। इस राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी चीजें हैं, उनका सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा देश कैसे धर्मनिरपेक्ष चलेगा, किसी की भावना आहत तो नहीं हो रही है, सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ तो नहीं रहा है, यह सुनिश्चित करना होगा।*

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा- कोई भी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय और पार्टी संविधान के तहत ही हो सकती है। पार्षदों ने यदि कुछ बोला है तो नोटिस देकर जवाब मांगें कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कहा।

● ***प्रवक्ता केके मिश्रा***- *जो राष्ट्रधर्म नहीं निभा सकते और वंदे मातरम् नहीं बोल सकते, वे पाकिस्तान में जाकर बस जाएं। यह पूरे विवाद को इंदौर में रहे एक विवादित अधिकारी ने हवा दी है।*

● ***अल्पसंख्यक प्रभारी छत्तीसगढ़ डॉ. अमीनुल सूरी***- *वंदे मातरम् का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसे अनिवार्य करना गलत है।*

● ***पार्षद राजू भदौरिया***- *यह पूरा विवाद फौजिया के पति शेख अलीम और महापौर के बीच हुई डील का नतीजा है। पहले वह राष्ट्रगीत गाती रही है, उसी दिन क्यों मना किया? यह पूरी साजिश है।*

नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी में मोहन सरकार

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● मध्यप्रदेश सरकार इस साल समय पर तबादला नीति लागू करने की तैयारी में है। 15 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने नई तबादला नीति के संकेत दिए। बैठक में मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। उन्होंने पाबंदी हटाने की मांग जोर-शोर से उठाई।

जीएडी अब नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगा। यह ड्राफ्ट अप्रैल के अंत तक कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद ही नीति को आधिकारिक मंजूरी मिलेगी।

हर साल की तरह इस बार भी तबादलों पर लगी रोक एक माह के लिए हटाई जाएगी। यह एक तय परंपरा बन चुकी है। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। किसी भी विभाग में कुल तबादले उस विभाग के कैडर के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे। यह सीमा मनमाने तबादलों पर लगाम लगाने के लिए तय की गई है। इससे प्रशासनिक अनुशासन बना रहेगा। सूत्रों के मुताबिक बीते साल 2025-26 में तबादले बेहद कम हुए। इसी वजह से इस बार नीति समय पर लाने का दबाव है। सरकार चाहती है कि

लंबित मामले जल्द निपटें। कई कर्मचारी लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। नई नीति से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी आसान होगी।

मध्यप्रदेश की नई तबादला नीति में प्रभारी मंत्रियों को पहले जैसे अधिकार वापस मिलेंगे। यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मंत्री अपने जिले के तबादलों की सूची में बदलाव कर सकेंगे।

जरूरी बात यह है कि मंत्री की मंजूरी के बिना कोई आदेश जारी नहीं होगा। यानी तबादलों पर अंतिम फैसला मंत्री के हाथ में होगा। इससे जिला स्तर पर जवाबदेही तय होगी।

जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के जरिए प्रस्तावित होंगे। यानी सीधे ऊपर से आदेश नहीं आएगा। पहले कलेक्टर प्रस्ताव बनाएगा। बैठक में मंत्रियों और विधायकों ने खुलकर तबादला पाबंदी हटाने की मांग रखी थी। इससे साफ है कि जनप्रतिनिधियों के अपने क्षेत्र में कर्मचारियों को लेकर काफी दबाव है। नई नीति से उन्हें यह मौका मिलेगा। जीएडी अब ड्राफ्ट नीति तैयार करेगा। अप्रैल के अंत तक इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नीति लागू होगी। इसके बाद एक माह की विंडो खुलेगी।

मोदी की सिद्धारमैया के साथ कानाफूसी पर शुरू हुई चर्चा

बेंगलुरु (एजेंसी) ● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर बेंगलुरु उतरे, तो एक तस्वीर वायरल हो गई। दरअसल, एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुखिया या प्रतिनिधि का मौजूद होना जरूरी होता है। कांग्रेसी सीएम सिद्धारमैया खुद पीएम का वेलकम करने माला लेकर खड़े थे। पारंपरिक टोपी और माला पहने प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक

सिद्धारमैया के कान में कुछ कहा और उसी समय तस्वीर क्लिक हो गई। बस फिर क्या था, चर्चा शुरू हो गई। हां, अब लोग इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कुछ कैप्शन लिखने को कह रहे हैं। यह तस्वीर चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि एक हफ्ते के भीतर पीएम कई बड़े कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करते दिखे थे। ऐसे में लोगों की उत्सुकता बढ़ गई।

प्रशासन के नियमों को जेब में लेकर चलता ठेकेदार

अवैध खनन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के गोलमोल जवाब

निलेश चौहान : 94250-77209

देपालपुर ● **दैनिक इंदौर संकेत**

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के नाम पर देपालपुर क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंगोरिया-देपालपुर रोड चौड़ीकरण का कार्य mprdc के आधीन निर्माण एजेंसी जैनको इंटरप्राइजेज कम्पनी ने क्षेत्र के तालाबों से मिट्टी निकाल कर गहरे कुओं में तब्दील कर दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि जनपद पंचायत सीईओ के आदेश और एसडीएम की मौजूदगी के बावजूद अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

नियमों को '15 फीट' गहरे गड्ढे में दफनाया-तालाबो में खनिज विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकारी या निजी कार्य के लिए मिट्टी निकालते समय गहराई 1 मीटर से 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला कलेक्टर और खनिज विभाग की विधिवत अनुमति अनिवार्य है। लेकिन गोकलपुर सहित क्षेत्र के कई तालाबों में ठेकेदार ने 15 से 20 फीट गहरे जानलेवा गड्ढे कर दिए हैं।

अधिकारियों की 'खानापूर्ति' या मिलीभगत?

मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत सीईओ पूजा मालाकार और एसडीएम प्रदीप सोनी मौके पर पहुंचे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल 'रस्म अदायगी' हुई। दावा बनाम हकीकत सीईओ पूजा मालाकार ने दावा किया कि उन्होंने मशीनें बंद करवा दी हैं, लेकिन धरातल पर पोकलेन और डंपर बेखौफ चलते पाए गए।

एसडीएम का अजीब तर्क: एसडीएम प्रदीप सोनी का कहना है कि सरकारी काम में उपयोग लेने के लिए तालाब से मिट्टी निकालने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है और न ही रॉयल्टी वसूली जाती है।

सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी काम के नाम पर पर्यावरण और जल संरचनाओं को नष्ट करने की छूट दी जा सकती है?

किसानों के लिए नियम, ठेकेदार को खुली छूट-स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई गरीब किसान अपने खेत या घर के लिए तालाब से एक ट्राली मिट्टी उठा ले, तो प्रशासन उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटका देता है। किसानों को मिट्टी के लिए पैसे और लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वहीं रसूखदार ठेकेदार बिना किसी अनुमति के पूरे के पूरे तालाब खोद रहे हैं और अधिकारी मूकदर्शक बने बैठे हैं।

प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए जनपद सीईओ पूजा मालाकार कभी काम रुकवा देते हैं तो कभी काम चालू करवा देते हैं देपालपुर एसडीएम प्रदीप सोनी भी नियम और अनुमति का पाठ पढ़ा रहे है लेकिन जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो अवैध खनन रोकने में प्रशासनिक अधिकारी सफल साबित हुए मुख्य बिंदु जो प्रशासन को कठघरे में खड़ा करते हैं? लापता खनिज अधिकारी क्षेत्र में सरेआम अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी कार्यालयों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं।?दो दिन की 'लुका-छिपी' शिकायत होने पर ठेकेदार दो दिन काम बंद करता है और फिर तीसरी रात से मशीने गरजने लगती हैं। सुरक्षा का खतरा 20 फीट गहरे गड्ढे भविष्य में मवेशियों और बच्चों के लिए काल बन सकते हैं।

अवैध खनन को लेकर जनपद सीईओ एसडीएम आमने सामने

आईडीए में एनओसी रैकेट सक्रिय : अफसरों की फर्जी साइन से हो रही है जमीनें मुक्त

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) में जमीन की एनओसी को लेकर एक बड़ा रैकेट चल रहा है। इसमें प्राधिकरण के ही कर्मचारी के मिले होने की बात सामने आई है। कर्मचारी खुद अधिकारियों के साइन कर एनओसी जारी करते हैं। इसके बाद टीएनसीपी में नक्शा मंजूरी के लिए भेजा जा रहा था।

यह खुलासा टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) अधिकारियों की जांच से हुआ है। इधर, आईडीए अधिकारियों का शक है कि विधि विभाग का बाबू शुभम श्रीवास्तव इस रैकेट से जुड़ा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जिस दिन से मामला सामने आया है, उस दिन से ही वह बिना सूचना के ऑफिस नहीं आया है। उसका फोन भी बंद है। घर से भी लापता है।

एनओसी और प्रारूप में साइन का अंतर-मामला योजना 97 पार्ट 4 बिजलपुर की जमीन का है। करीब 20 हजार वर्गफुट से ज्यादा यह जमीन आईडीए की योजना में शामिल है। हाल ही में जमीन मालिक की ओर से टीएनसीपी के समक्ष ले-आउट स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। दस्तावेज परीक्षण में पता चला कि आईडीए से जारी की गई एनओसी और प्रारूप में साइन का अंतर है।

यह एनओसी प्लानिंग और भू-अर्जन दोनों विभागों से जारी हुई थी। टीएनसीपी अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने आईडीए अधिकारियों को फोन किया। तब पता चला कि यहां से इस तरह की कोई एनओसी जारी नहीं की गई है।

1.5 महीने पहले पहली बार भेजी गई फर्जी एनओसी-टीएनसीपी अधिकारी शुभाशीष बनर्जी ने बताया कि हमारे पास उस जमीन का नक्शा मंजूरी के लिए फाइल आई थी। हमने एनओसी मांगी तो उन्होंने एनओसी में बताया कि यह जमीन आईडीए की स्कीम में नहीं है। हमें एनओसी पर कुछ साइन ऐसे लगे कि वह गलत हैं। हमने फोन कर पूछा कि जमीन की एनओसी हमारे पास आई है।

इस पर आईडीए अधिकारी ने कहा कि हमारे यहां से जारी नहीं हुई है। यह पता चलने पर हमने उसे कैंसिल कर दिया। 4 से 5 दिन पहले फिर हमारे पास यह फाइल आई, तब हमें दोबारा शक हुआ। हमने आईडीए को एनओसी की फोटो कॉपी भेजकर पूछा कि इसकी पुष्टि करें कि यह आपके यहां से जारी हुई है या नहीं। इस पर आईडीए ने फिर से एनओसी जारी करने से मना कर दिया।

आईडीए अधिकारी के किए नकली साइन-भू-अर्जन अधिकारी सुदीप मीणा ने बताया कि नकली साइन कर फर्जी एनओसी बनाने का मामला हमारे सामने आया है। मेरे भी नकली साइन बनाकर फर्जी एनओसी बनाई गई है। मेरे से पहले कंट्री प्लानिंग के अधिकारी के साइन किए गए थे।

स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच जिस तरह से दिन का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए इंदौर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का कर दिया है। किसी भी स्थिति में बच्चों को 12 बजे तक स्कूल में नहीं रखा जाए। गौरतलब है कि इंदौर के आसपास लगभग सभी जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन हो चुका था। इसको लेकर यही संभावना जताई जा रही थी कि बहुत जल्द ही इंदौर में भी इस तरह के आदेश जारी होंगे।

न्यूज ब्रीफ

- संसद : बिल से पहले स्पीकर संग अमित शाह की बड़ी बैठक
- IRCTC घोटाला : लालू परिवार के खिलाफ अब 6 मई को आएगा फैसला
- परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही : मंत्री किरण रिजिजू
- लखनऊ : दो बच्चों की जलकर मौत, देर रात 50 से ज्यादा झुग्गियों में लगी थी आग

न्यूज ब्रीफ

ओंकारेश्वर में 17 से 21 तक 'आचार्य शंकर प्रकटोत्सव' मनेगा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य के प्रकटोत्सव वैशाख शुक्ल पंचमी के उपलक्ष्य में 'एकात्म पर्व' का पंच दिवसीय भव्य आयोजन 17 से 21 अप्रैल तक ओंकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर स्थित 'एकात्म धाम' में आयोजित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम का शुभारंभ 17 अप्रैल को प्रात: 9.30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, द्वारका पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी के पावन सान्निध्य तथा विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता भिड़े, स्वामी शारदानंद सरस्वती की उपस्थिति में होगा। आगामी 21 अप्रैल को शंकरावतरणम् में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि और चिन्मय मिशन के स्वामी तेजोमयानंद सरस्वती, दक्षिणामूर्ति मठ, के प्रमुख स्वामी पुण्यानंद गिरि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी. राम सुब्रमण्यम प्रमुख रूप से सम्मिलित होंगे।

'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के पूर्व नि:शुल्क लाइव योग अभियान प्रारंभ

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● आयुष विभाग इन्दौर द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया जाएगा। उक्त संबंध में आयुष मंत्रालय भोपाल के द्वारा आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में इसके पूर्व जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फ्री लाइव योग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. हंसा बारिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन के दैनिक जीवन में योग को शामिल करना है। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों के लिए निशुल्क 14 दिवसीय योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका प्रसारण ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 27 मई को समाप्त होगा। योग सत्रों में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर संपर्क कर सकते हैं या मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की वेबसाइट पर जाकर निशुल्क पंजीयन कर सकते हैं।

सत्र 2025-26 की पीजी, डिप्लोमा, यूजी और चार वर्षीय पाठ्यक्रमों के अंक 10 तक लेंगे

परीक्षा प्रणाली को लेकर डीएवीवी नई पारदर्शिता नीति करेगा लागू

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता। समय-सीमा, डिजिटल निगरानी और स्पष्ट जवाबदेही के जरिए विवि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में विवि ने सत्र 2025-26 की परीक्षाओं को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं।

डिजिटल सिग्नेचर को किया अनिवार्य: परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि अंक प्रविष्टि की यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि परीक्षा परिणामों की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चि करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के तहत विभागाध्यक्षों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। सीसीई अंकों के संधारण और सत्यापन के लिए विभागाध्यक्ष के डिजिटल सिग्नेचर को

अनिवार्य किया गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया पर सूक्ष्म निगरानी रखी जा सके। यदि किसी कारणवश विभागाध्यक्ष का डिजिटल सिग्नेचर निष्क्रिय रहता है, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से यह कार्य पूरा किया जाएगा।

अनुमति के बगैर नहीं बदल सकेंगे परीक्षक : परीक्षा नियंत्रक ने प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों के नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई परीक्षक नियुक्ति स्वीकार करने से मना करता है या असमर्थता जताता है, तो इसकी सूचना तुरंत विवि के गोपनीय विभाग को दी जाए। साथ ही विवि की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी इसकी जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि बिना गोपनीय विभाग की पूर्व अनुमति के किसी भी परीक्षक को बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी महाविद्यालय की ओर से मनमाने तरीके से परीक्षक में बदलाव किया जाता है, तो संबंधित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रबंधन का मानना हैं कि इस तरह के कड़े प्रावधानों से परीक्षा प्रक्रिया में अनुशासन और विश्वसनीयता बनी रहेगी।

इन विषयों के लिए लेना हैं अंक

पीजी, डिप्लोमा, यूजी और चार वर्षीय पाठ्यक्रमों के सीसीई, प्रायोगिक और प्रोजेक्ट अंकों को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 10 मई तक लिए जाएंगे। प्रबंधन ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय-सीमा में विद्यार्थियों के अंक अनिवार्य रूप से एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड करें। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि एमबीए पूर्णकालीन पाठ्यक्रम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर, एफए, आईबी, बीई, एमएम, एचए, फॉरेन ट्रेड व एमएससी (सीएस, आईटी और बायोटेक्नोलॉजी) के चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के अंक इस प्रक्रिया में शामिल हैं। इसके अलावा एमएसडब्ल्यू के दूसरे और चौथे सेमेस्टर, पीजीडीसीए, पीजीडीएफडीएम और पीजीएचआरडी के दूसरे सेमेस्टर के साथ ही बीएचएम के दूसरे, चौथे, छठवें और आठवें सेमेस्टर, बीजे के दूसरे सेमेस्टर के नियमित, भूतपूर्व और एटीकेटी प्राप्त विद्यार्थियों के अंक भी इसी समय-सीमा में लिए जाएंगे।

प्रवेश नहीं दिया तो करें शिकायत

आरटीई में संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● जिला प्रशासन ने कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन पर नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) में एडमिशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अभिभावक जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0731-2431117 पर अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन कार्यालयीन समय में संचालित रहेगी।

अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) में एडमिशन संबंधी किसी भी तरह की समस्याओं को इस नम्बर पर दर्ज करा सकते हैं। चयनित बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं देने तथा किसी भी तरह से परेशान करने वाले स्कूलों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि एडमिशन की आखिरी तारिख 15 अप्रैल थी। इसी हेल्पलाइन पर स्कूलों में किताबों, स्टेशनरी एवं यूनिफॉर्म के नाम पर अधिक कीमत वसूली या अभिभावकों को जबरन खरीद के लिए बाध्य किए जाने की शिकायतें भी की जा सकती है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नागरिक शैक्षणिक के साथ ही अन्य शिकायतें भी इसी हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालयीन समय में दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे सभी तरह की अनियमितता की सूचना तुरंत दें, ताकि शिक्षा पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

आयुक्त ने कई जोनों में किया निरीक्षण, गंदगी मिलने पर कार्रवाई

सफाई में लापरवाही दरोगाओं का वेतन कटा

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जोन क्रमांक 18, 22, 10, 13 एवं 15 के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई में लापरवाही और कई स्थानों पर कचरा-गंदगी पाए जाने पर संबंधित दरोगाओं के एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जोन 18 के तीन इमली बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बेहद खराब पाई गई। इस पर आयुक्त ने केयरटेकर को फटकार लगाते हुए संबंधित एजेंसी पर रु.10 हजार की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही तीन इमली ब्रिज के नीचे और आसपास के क्षेत्र में नियमित सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने आसपास की दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान झोनल अधिकारी अतिक खान द्वारा डस्टबिन नहीं रखने वाली दो दुकानों पर 1,000- 1,000 रु. का स्पॉट फाइन लगाया गया। जोन 22 के वार्ड 31 में सत्य साई चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल तक तथा जोन 10 के वार्ड 39 में लाभगंगा क्षेत्र के पास स्थित शौचालय और गलियों में गंदगी मिलने पर संबंधित दरोगाओं के वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

इसी तरह जोन 18 के वार्ड 64 में एबी रोड स्थित आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के सामने तथा जोन 15 के वार्ड 83 में गोंदवले धाम से चंदन नगर तिराहे के बीच ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कचरा मिलने पर भी कार्रवाई की गई। जोन 13 के अंतर्गत चौइथराम सब्जी मंडी और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भी सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने और संबंधित दरोगा का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। नगर निगम द्वारा की गई इस सख्ती से साफ संकेत मिल रहा है कि शहर में स्वच्छता को लेकर अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विधायक शुक्ला ने किया वैदिक रीति रिवाज से कन्यादान

विवाह सम्मेलन का पूरा खर्च विधायक ने उठाया

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● सर्वजातीय सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजन समिति के दीपेन्द्रसिंह सोलंकी ने बताया कि क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला द्वारा आज गांधी हॉल में निशुल्क सर्वजातीय सामुहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न हुआ। आयोजन में संत अन्ना जी महाराज, श्री श्री 1008 दादू महाराज, परम पूज्य नाना जी महाराज, भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, गोपी कृष्ण नेमा, राजेंद्र शुक्ला, मुग्धा शुक्ला, स्वाति कशीद, आंजनेय शुक्ला, यश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आयोजन

समिति ने बताया कि विधायक गोलू शुक्ला द्वारा अनूठी पहल की गई, विधानसभा क्षेत्र क्र.3 के निवासी ऐसे माता-पिता जो अपनी कन्या का विवाह करवाने में असमर्थ हैं या आर्थिक रूप से कमजोर है, उन कन्याओं का विवाह सनातनी विधायक गोलू शुक्ला द्वारा करवाया गया। विधायक गोलू शुक्ला ने बताया कि हमने संकल्प लिया था, कि क्षेत्र की विवाह योग्य निर्धन, दिव्यांग और अनाथ कन्याओं का निशुल्क विवाह करवाएंगे, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए सनातन हिन्दू समाज सामुहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए महिलाओं ने निकाली स्कूटी रैली

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जगह जगह आयोजन हो रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज देवी माँ अहिल्या मातृशक्ति मंच द्वारा देवी अहिल्या प्रतिमा राजवाड़ा चौक से गांधी प्रतिमा तक स्कूटी रैली निकाली गई। रैली में भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, भाजयुमो प्रदेश महामंत्री विप्लव जैन, शिवानी अड़सपुरकर, निधि बंग सहित बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देने के लिए स्कूटी

पर सवार होकर रीगल स्थित गांधी प्रतिमा पहुंची। रैली की शुरूवात नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और पदाधिकारियों ने राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। इसके पश्चात स्कूटी रैली प्रारंभ हुई। रैली कृष्णापूरा पूल से होते हुए जेल रोड, एम जी रोड होते हुए रीगल चौराहे स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंची।

हिंदू नाबालिग लड़की के साथ पकड़ाए मुस्लिम युवक , बजरंगियों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा...

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शहर के विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित आनंद मोहन माथुर सभा ग्रह के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ संदिग्ध स्थिति में पकड़ लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा हुआ।

बताया जा रहा है कि विभाग सह संयोजक अविनाश कौशल को सूचना मिली थी कि एक युवक एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ पिछले कुछ दिनों से इंदौर में रह रहा है और अलग-अलग जगहों पर किराए का कमरा तलाश रहा है। सूचना के आधार पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक को पकड़ने के बाद स्थानीय रहवासियों में आक्रोश फैल गया और उसकी पिटाई कर दी गई। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बन गई।

सूचना मिलते ही विजय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से युवक को छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया। पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब लड़की के माता-पिता ने सामाजिक बदनामी के डर से एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायती आवेदन सौंपा है।

मध्यप्रदेश राजीव विकास केंद्र की 125 पदाधिकारियों की घोषणा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया है की आगामी नगर निगम विधानसभा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने एवं भाजपा से मैदानी स्तर पर मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र की 125 सदस्य पदाधिकारियों की घोषणा की गई है जिसमें 1 प्रदेश कोषाध्यक्ष एक प्रदेश मीडिया प्रभारी 1 संस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष 1 लोकसभा अध्यक्ष 6 प्रदेश प्रवक्ता 35 प्रदेश उपाध्यक्ष 35 प्रदेश महामंत्री 45 प्रदेश सचिव की नियुक्ति की गई है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी एवं शहर जिला अध्यक्षों के मार्गदर्शन में कार्य करेगें। यादव ने कहा है की संगठन में पुराने लोग भी होते हैं और नए भी सभी मिलकर कम करते हैं तभी संगठन सफल और मजबूत होता है युवा शक्ति का उतना ही महत्व है जितना बुजुर्गों के अनुभव का राज्य एवं जिला शहर स्तर पर प्रयास होना चाहिए की सभी को हम साथ लेकर चले जी से जहां महत्व दे सकते हैं दे जब हमारा आकर्षण बढ़ेगा तब अभी भाजपा भी टूटेगी प्रयास होना चाहिए की महत्वाकांक्षाओं को कांग्रेस पार्टी के हित में ताकत बनाए। यादव ने बताया है की कार्य करने में 1 मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष बजाज 1 मीडिया प्रभारी नीतिश भरद्वाज 1 संस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार सत्येंद्र वर्मा सत्येन 1 लोकसभा अध्यक्ष प्रतिक मित्तल 6 प्रदेश प्रवक्ता शंकर नैनवा सुनील गोधा तेजप्रकाश राणे मनीष मोदी सन्नी पठारे रमेश घाटे।

सोसायटी प्रबंधक के पक्ष में एसडीएम कार्यालय पहुंचे किसान

एसडीएम से की निष्पक्ष जांच की मांग

दैनिक इंदौर संकेत

देपालपुर ● कनवासा सहकारी समिति में समर्थन मूल्य खरीदी के दौरान रिश्वत लेने तथा किसानों की ट्रॉलियां रोकने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें किसानों ने पूर्णत: भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बताया है। इसी के विरोध में आज बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान, भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

देपालपुर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव चंदनसिंह बड़वाया, सरपंच पर्वत सिंह बड़वाया सहित अनेक किसान उपस्थित रहे। किसानों ने एकजुट होकर स्पष्ट किया कि कनवासा सहकारी समिति के प्रबंधक श्री मनोज शर्मा पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और यह उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है। किसानों ने कहा कि मनोज शर्मा का कार्यकाल हमेशा पारदर्शी, ईमानदार और किसानों के हित में रहा है। उन्होंने कभी किसी किसान से किसी प्रकार की अवैध मांग नहीं की, बल्कि वे हमेशा किसानों की सुविधा और सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यहां तक कि किसानों ने यह भी कहा कि वे किसी से 'चाय तक स्वीकार नहीं करते', जो उनकी कार्यशैली की ईमानदारी को दर्शाता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि बड़े कांटे पर तुलाई को लेकर जो बातें प्रचारित की जा रही हैं, वे भी तथ्यहीन हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई वैधानिक आदेश लागू नहीं है।

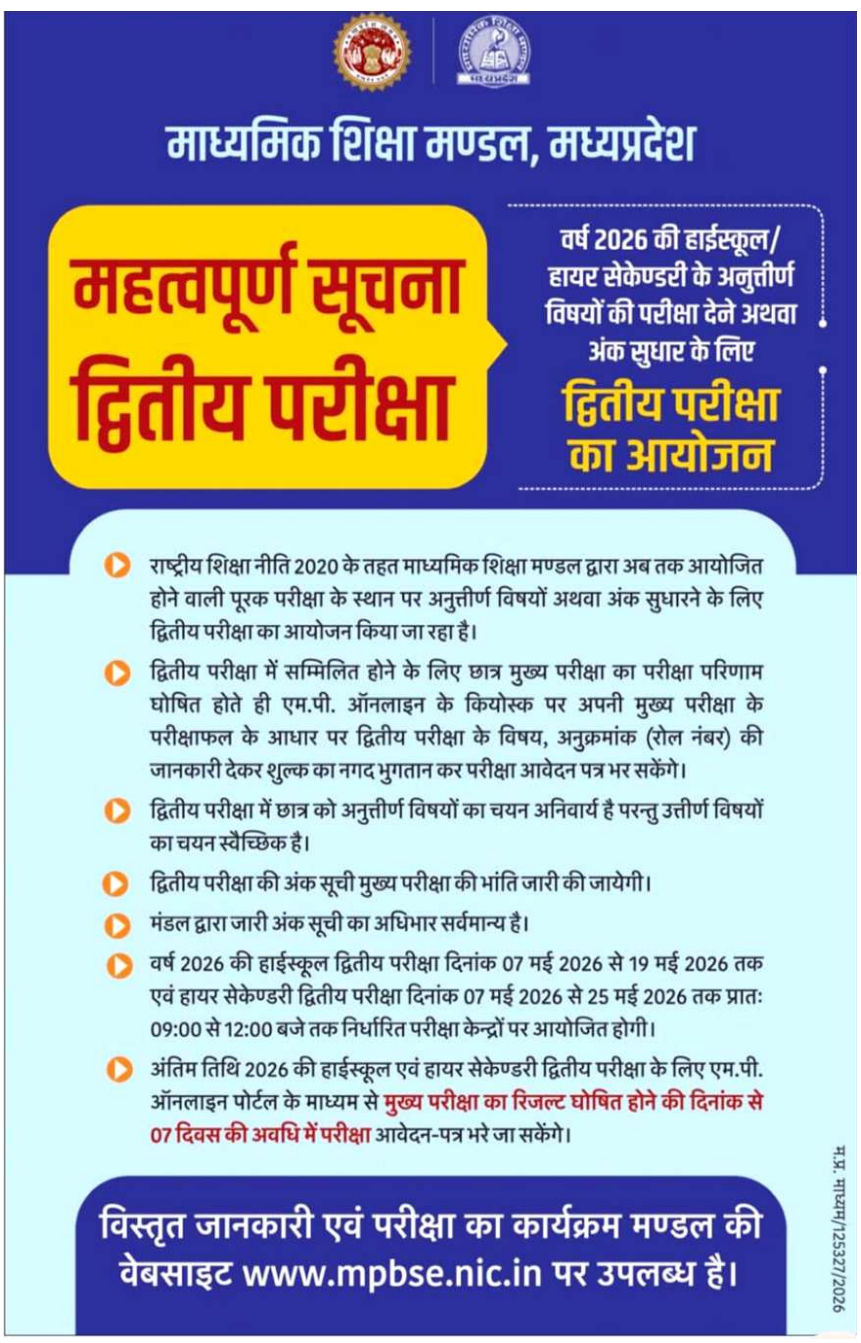

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, गुरुवार 16 अप्रैल 2026

भोजशाला केस : हाई कोर्ट में गूंजा हदीस का हवाला, वकील बोले- 'इस्लाम में भी जबरन जमीन पर मस्जिद बनाना गलत'

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● धार भोजशाला का धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने के लिए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में बुधवार से एक बार फिर नियमित सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी की ओर से एडवोकेट मनीष गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कोर्ट में हदीस का हवाला देते हुए कहा कि इस्लामिक कानून कहता है कि जबरन जमीन लेकर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता, अगर कहीं ऐसा हुआ भी है तो उस जमीन को लौटाने के उदाहरण भी इस्लाम में हैं। हिंदू कानून के अनुसार एक बार मंदिर रहा स्थल हमेशा मंदिर ही रहता है। ये दोनों ही बातें इंगित करती हैं कि भोजशाला वाग्देवी का मंदिर ही है।

ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई वाग्देवी की मूर्ति पर जो विवरण अंकित है वह बताता है कि मूर्ति की स्थापना राजा भोज ने की थी।

धार भोजशाला में इसके पहले भी कई बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का सर्वे हो चुका है। हर बार सर्वे में यहां से देवी-देवताओं की मूर्तियां, आकृतियां, चित्र मिले हैं जो किसी मस्जिद में हो ही नहीं सकते क्योंकि इन्हें वहां रखने की अनुमति नहीं होती। भोजशाला मंदिर है इसलिए याचिकाकर्ता को 24 घंटे पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। बुधवार को याचिकाकर्ता तिवारी की ओर से तर्क पूरे हो गए। गुरुवार को अन्य याचिकाकर्ता अंतरसिंह की ओर से तर्क रखे जाएंगे।

बुधवार दोपहर ठीक ढाई बजे न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगलपीठ के समक्ष भोजशाला मामले में सुनवाई शुरू हुई। एडवोकेट गुप्ता ने शुक्रवार को अधूरी रही बहस आगे बढ़ाते हुए कोर्ट को बताया कि वर्ष 1908 में प्रकाशित राजपत्र में कहा है कि भोजशाला में जो पत्थर लगे हैं उन पर लिखा है कि यहां बसंत पंचमी के दिन राजा भोज द्वारा लिखे गए नाटक का मंचन किया जाता था।

हवन कुंड और वाग्देवी की मूर्ति का मिलान

मूर्ति की मुद्रा क्या होनी चाहिए, पुस्तक में बताया है कि हवन कुंड की लंबाई-चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। भोजशाला में बने हवन कुंड की लंबाई-चौड़ाई उतनी ही है जो राजा भोज द्वारा लिखी गई पुस्तक में लिखी है। वाग्देवी की ब्रिटिश संग्रहालय में रखी मूर्ति पर भी उल्लेखित है कि इसे राजा भोज ने स्थापित किया था। यह मूर्ति भोजशाला से ही ब्रिटिश संग्रहालय पहुंचाई गई थी। इन बातों से सिद्ध होता है कि भोजशाला का अस्तित्व मस्जिद से बहुत पहले से है। भोजशाला के सर्वे में अब तक 150 से ज्यादा मूर्तियां मिल चुकी हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि भोजशाला मंदिर ही है।

एडवोकेट गुप्ता ने राजा भोज द्वारा लिखी गई पुस्तकों का उल्लेख किया और बताया कि इन पुस्तकों में बताया है कि हवन कुंड कैसा होना चाहिए, हवन कुंड का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति की साइज कितनी होनी चाहिए।

एडवोकेट गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष इस्लामिक कानून का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक कानून के अनुसार किसी की जमीन जबरन लेकर उस पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए जब जबरन ली गई जमीन लौटाई गई हो। भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट में चार याचिकाएं और एक अपील चल रही हैं। इन सभी में सुनवाई एक साथ हो रही है। 6 अप्रैल से हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में अब तक दो याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और कुलदीप तिवारी की ओर से तर्क रखे जा चुके हैं। मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

नवलखा कांटाफोड़ मंदिर से जुड़े भक्तों की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवलखा स्थित मनकामेश्वर कांटाफोड़ शिव मंदिर के भक्तों का जत्था आगामी 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के लिए रेल मार्ग से प्रस्थित होगा। पिछले कई वर्षों से कांटाफोड़ मंदिर ट्रस्ट की ओर से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर लंगर सेवा और इंदौर तथा मालवांचल से पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का सिलसिला चला आ रहा है। इस बार भी यह यात्रा थर्ड एसी कोच से होगी। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु बिंदल, टीकमचंद गर्ग एवं संयोजक बीके गोयल ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में मंदिर से जुड़े भक्तों द्वारा उत्साह दिखाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से मंदिर ट्रस्ट से जुड़े भक्त अमरनाथ यात्रा में शामिल तो हो ही रहे है, यात्रा मार्ग पर लगने वाले लंगर में भी अपनी सेवाएँ देते आ रहे हैं।

गौसेवा भारती में पिंगले अध्यक्ष, बोहरा बने महामंत्री

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● गौसेवा भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री कैलाशचंद्र खंडेलवाल ने इंदौर इकाई के संगठन मंत्री निलेश गंगराडे की अनुशंसा पर गौसेवा भारती इंदौर की वर्ष 2026-27 के लिए 71 सदस्यीय नवीन कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सुरेश पिंगले को अध्यक्ष, उपेन्द्र बोहरा को महामंत्री एवं पंकज अग्रवाल को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया है। नई कार्यकारिणी में 3 संयुक्त महामंत्री, 9 उपाध्यक्ष, 11 मंत्री, 11 सह मंत्री, 16 कार्यकारिणी सदस्य, प्रचार मंत्री तथा 16 विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किए गए हैं। खंडेलवाल ने शहर की नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा के साथ ही राज्य शासन को गौहत्या बंदी को लेकर कड़े कानून बनाने पर धन्यवाद दिया है। संगठन के अध्यक्ष सुरेश पिंगले एवं महामंत्री उपेन्द्र बोहरा ने 27 अप्रैल को होने वाले गौ सम्मान आन्दोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि देश में केरल, कर्नाटक और बंगाल जैसे प्रान्तों में आज भी गौ हत्या के लिए मंडी लगती है और प्रतिदिन हजारों गौ वंश का क़त्ल किया जा रहा है। गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर गौ वंश के हत्यारों को फांसी की सजा का प्रावधान करने तथा देश के हर जिले में गौ-अभ्यारण्य बनाने की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गौ सेवा भारती द्वारा 27 अप्रैल को देशव्यापी व्यापक आन्दोलन किया जाएगा जिसके तहत इंदौर में भी उक्त आन्दोलन चलाया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ मार्गदर्शक हुकुमचंद सावला, अशोक गुप्ता हिन्दुस्तानी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने नए पदाधिकारियों का स्वागत किया।

श्री परशुराम सेना के नेतृत्व में पश्चिम क्षेत्र में रुक्मिणी नगर में प्रभातफेरी का आयोजन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● 18 अप्रैल को बड़े गणपति से राजबाड़ा तक परशुराम सेना द्वारा ब्राह्मण संस्कार यात्रा गौ माता के नेतृत्व में निकालने और सर्व ब्राह्मण समाज बंधुओ को एकजुट होकर संस्कारों का समाज में सिंचन करने और सभी को मिलकर समाज का विकास और एक दूजे के सुख दुख में साथ खड़े हो उक्त उद्देश्य को लेकर आज भगवान परशुराम जी की प्रभात फेरी का पश्चिम क्षेत्र एयरपोर्ट रोड के रुक्मिणी नगर से किया गया।

बड़े ही हर्ष का विषय है कि भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर परशुराम सेना द्वारा पूरे इंदौर शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में भगवान परशुराम जी की प्रभात फेरी का दिव्य आयोजन निरंतर चल रहा है इस कड़ी में पश्चिम क्षेत्र में यह प्रभात फेरी का आयोजन आज परशुरामजी की भव्य प्रभात फेरी निकाली गयी।

पिंक फ्लॉवर स्कूल, इंदौर का शानदार बोर्ड परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों ने रचा कीर्तिमान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● पिंक फ्लॉवर स्कूल, इंदौर ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं। पिछले दस वर्षों से विद्यालय निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन करता आ रहा है और इस वर्ष भी विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन तथा शिक्षकों एवं अभिभावकों के सहयोग से सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं।

कक्षा 12वीं के परिणामों में आकांक्षा मौर्य ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आकांक्षा भिलवारे ने 93.20% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि पलक बुनकर ने 93% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष 12 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, वहीं 116 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। विद्यालय का कुल परिणाम 95% रहा। कक्षा 10वीं में हरिओम पाल ने 97.60% अंक प्राप्त कर विद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया। चंचल मोहानिया एवं श्रेयश डोलिया ने 97% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि अनीकेत साकल्ले ने 96.80% अंक प्राप्त किए। इस वर्ष 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए तथा 100 विद्यार्थियों ने 70% से अधिक अंक हासिल किए, जो विद्यालय की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को दर्शाता है। कुल 163 विद्यार्थियों में से 145 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की, जिससे विद्यालय का कुल परिणाम 98% रहा।

ग्रीष्म ऋतु में रखें सावधानी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने और गर्म हवा लगने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। वृद्ध, बच्चे, खिलाड़ी, धूप में काम करने वाले श्रमिक सर्वाधिक खतरे में रहते हैं। पसीना न आना, गर्म-लाल एवं शुष्क त्वचा, मतली, सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, उल्टियां होना, बेहोश हो जाना एवं पुतलियां छोटी हो जाना अत्यधिक गर्मी से प्रभावित होना व तापघात के प्रमुख लक्षण एवं संकेत हैं। गर्मी व तापघात से बचाव के लिए खूब पानी पिएं व खाली पेट न रहें, शराब व चाय-कॉफी के अधिक सेवन से बचें, ठण्डे पानी से नहाएं, सर ढके व हल्के रंग के ढीले व पूरी बांह के कपड़े पहने, बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़े, दिन में 12 से 04 के मध्य बाहर जाने से बचें, धूप में नंगे पाँव न चलें, बहुत अधिक भारी कार्य न करें।

मेधावी बच्चों को मिलता है 25 हजार का प्रोत्साहन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● राज्य शासन द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 'सुपर 5000 योजना' वर्ष 2013 से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ?25 हजार की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार, राज्य मेरिट में टॉप 5000 योजना में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह लाभ मिलेगा। कक्षा 10वीं में राज्य स्तर की टॉप 5000 योजना में मेरिट में स्थान होना आवश्यक है, जबकि कक्षा 12वीं में अपने-अपने संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की टॉप 5000 मेरिट योजना में शामिल होना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके माता या पिता परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व MPBOCW में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं तथा जिन्होंने मध्यप्रदेश बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है। आवेदन के लिए श्रम सेवा पोर्टल www.labour.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मेरिट प्रमाण पत्र एवं विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा संलग्न करना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले वर्ष 31 मार्च तक आवेदन करना होगा, अन्यथा वह इस योजना के लाभ से वंचित हो सकता है।

परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधासागरजी का समंग्र जैन समाज से आह्वान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● प्राकृत शोध संस्थान, बासोकुंड. वैशाली को बिहार सरकार द्वारा बंद करने पर परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने समाज, सरकार एवं विद्वानों का आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान में हमारे

आयतनों पर प्रहार हुए, अब हमारे संस्थानों पर प्रहार प्रारंभ हुआ है। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने कहा कि परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सारे भारत की समाज को चेताया है कि भगवान महावीर के जन्मस्थल पर स्थित इस संस्थान जहाँ से सैकड़ों विद्वान निकले, उस संस्थान को बंद कर दिया जाये और समाज कुंभकर्णी नींद सोती रहे, ये बहुत बड़ा जैन धर्म संस्कृति के लिए दुर्भाग्य है. । गुरु देव ने समस्त भारतवासियों समाज जन से समस्त विद्वानों, समाज एवं श्री मंतों से कहा कि अपने अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं शिक्षामंत्री से समाज जन अपना विरोध दर्ज कराएं।

शिक्षकों-युवा पेशेवरों के लिए 'द एडुस्फेयर लीडरशिप मीट' का सफल आयोजन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● जीसीसी स्कूल ने हाल ही में 'द एडुस्फेयर लीडरशिप मीट'का सफल आयोजन किया। यह एक स्पेशल राउंडटेबल सत्र था, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग और शैक्षणिक जगत के बीच की दूरी को कम करना था। इस पहल का लक्ष्य कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए प्रमुख बड़ी फर्मों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में करियर के सुरक्षित अवसर सुनिश्चित करना है।जीसीसी स्कूल के कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) मनप्रीत सिंह मन्ना ने कहा, 'जीसीसी स्कूल का हमारा उद्देश्य है कि नेशनल फाइनेंस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से वाणिज्य के छात्रों को AEIAP जैसे कार्यक्रमों में प्रवेश दिलाकर उन्हें भविष्य के कुशल पेशेवरों में बदलना है। हम इंदौर और संपूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र के छात्रों के लिए करियर में विकास की अपार संभावनाएं देखते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के माध्यम से हम उन्हें बिग फर्मों और प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश दिलाने के लिए तैयार करते हैं, जहाँ योग्य उम्मीदवारों के लिए 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से शुरू होने वाले शुरुआती पैकेज के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 18-19 को

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मधुमेह एवं मोटापे जैसे रोगों से मुक्ति एवं राहत दिलाने के उद्देश्य से अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति, बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन एवं हेल्थ फॉर भारत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में श्रीमती नीना देवी अग्रवाल की पुण्य स्मृति में चलाए जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के अंतर्गत छठां शिविर 18-19 अप्रैल को एयरपोर्ट रोड स्थित बाबाश्री रिसोर्ट पर सुबह 8 बजे से आयोजित होगा। शिविर की तैयारियों को लेकर पश्चिमी क्षेत्र के 25 अग्रवाल संगठनों की बैठक में शिविर का लाख उठाने के लिए अधिक से अधिक समाज बंधुओं को प्रेरित करने का संकल्प लिया गया।

बाबा साहब आंबेडकर जयंती मनाई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● महू रोड़ पर सिलिकॉन सिटी स्थिति भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं .उनके चित्र पर माल्यार्पण कर जन्मदिन बड़े उत्साह उमंग से मनाया। इस अवसर पर ग्रुप द्वारा बाबा साहब की जन्मस्थली महू की ओर जा रहे अनुयायीयों के लिए ठंडा मीठे छाछ एवं शीतल जल का वितरण पूरे दिन किया गया। संस्था के वरिष्ठ सदस्य जितेन्द्र यादव ने बताया हमारे जागरण ग्रुप द्वारा ये कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। जिसमें सभी सदस्य तन मन धन से सहयोग करते हैं। संविधान की रक्षा के साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों की यथा संभव सहायता करें उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करें, उनको उठाने के लिए उनका मार्गदर्शन करें।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत

आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

सम्पादकीय

म्यूजिक इवेंट्स की आड़ में फैलता नशे का जाल, युवाओं की जिंदगी पर गहराता खतरा

देश में महानगरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में नशीले पदार्थों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा और गहरा प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ रहा है, जो उनके भविष्य और जान दोनों को खतरे में डाल रहा है। यह केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बड़ी चुनौती बन गया है। युवाओं के सामूहिक रूप से नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए विशेष आयोजन की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। मगर, अब इस तरह के आयोजनों का स्वरूप भी बदल रहा है।

ऐसी ही एक घटना हाल ही में मुंबई के गोरेगांव में सामने आई, जहां नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से प्रबंधन संस्थान में पढ़ाई करने वाले दो विद्यार्थियों की मौत हो गई। ये दोनों अपने दोस्तों के साथ एक संगीत कार्यक्रम में आए थे। सवाल है कि जब नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और खरीद के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान है, तो फिर युवाओं की इन तक आसानी से पहुंच कैसे संभव हो पा रही है?

यह बात छिपी नहीं है कि नशीले पदार्थों की बिक्री और इनके सेवन के लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। 'रेव पार्टी' की बजाय अब संगीत कार्यक्रमों की आड़ में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक, गोरेगांव में संगीत कार्यक्रम में भाग लेने आए जिन दो छात्र-छात्रा की मौत हुई, वे पहले से नशा करके आए थे और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान फिर से नशीले पदार्थ का सेवन किया।

यह बेहद चिंताजनक है कि पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन की आड़ में युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से प्रयास करने की इच्छाशक्ति कहीं नजर नहीं आती है। जबकि युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। हैरानी की बात है कि मुंबई जैसे महानगर में संगीत कार्यक्रमों की अनुमति देने से पहले प्रशासन की ओर से जांच और निगरानी की जरूरत महसूस नहीं की जाती है। जब तक सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर सतर्कता नहीं बरती जाएगी, तब तक यह समस्या हल नहीं हो पाएगी।

आमतौर पर नशा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यह आदत कब लत में तब्दील हो जाए, पता नहीं चलता। आदत को एक सकारात्मक अवधारणा के तौर पर देखा जाता है, जबकि लत या व्यसन एक नकारात्मक अवधारणा है। यह एक मनोविकार है, क्योंकि जिस नशे के सेवन की लत लग जाए, उसके बिना जीवन की निरंतरता असंभव दिखाई देती है। आदत बदलना संभवत: आसान हो सकता है, पर लत से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल लगता है। चिकित्सक भी मानते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन अनेक बीमारियों की जड़ है।

हाथियों की विरासत : जैव विविधता और पर्यावरण का अनमोल हिस्सा

(16 अप्रैल हाथी बचाओ दिवस पर विशेष आलेख)

पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान, विशालकाय और सामाजिक जीवों में से एक हाथी को 'पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर' कहा जाता है। इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और इनके घटते अस्तित्व को बचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को 'हाथी बचाओ दिवस' मनाया जाता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान समय में हाथी अनेक गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें अवैध शिकार (विशेषकर हाथीदांत के लिए), वनों की कटाई, प्राकृतिक आवास का विनाश, मानव-हाथी संघर्ष तथा जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। हाथी जंगलों, घासभूमियों और जल स्रोतों के संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है।

सुनील कुमार

पाठकों को जानकारी देता चलूं कि हाथी पारिस्थितिकी तंत्र(इको-सिस्टम) को कई तरीकों से समृद्ध करते हैं।मसलन, वे फलों और पौधों को खाकर लंबी दूरी तय करते हैं और अपने मल(लीद) के माध्यम से बीजों का प्रसार करते हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है और वनों का विस्तार बना रहता है। घने जंगलों में चलते समय वे टहनियाँ और झाड़ियाँ तोड़ते हैं, जिससे वन का घनत्व कम होता है और सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुँचता है, जिससे छोटे पौधों और घास को बढ़ने का अवसर मिलता है और जैव विविधता बनी रहती है। सूखे के समय हाथी अपनी सूंड और पैरों से जमीन खोदकर पानी निकालते हैं, जिससे बने गड्ढे अन्य जानवरों के लिए भी जल स्रोत बन जाते हैं। इसके अलावा हाथियों के चलने से प्राकृतिक मार्ग (कॉरिडोर) बनते हैं, जो अन्य जीवों की आवाजाही को सरल बनाते हैं। उनका मल मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान कर उसे उर्वर बनाता है और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है।

बहरहाल, यदि हम यहां पर हाथियों से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो भारत में हाथियों की उपस्थिति मुख्य रूप से कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में पाई जाती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट (2017) के अनुसार भारत में लगभग 29,000-30,000 जंगली हाथियों का अनुमान था, जबकि 2025 की नवीनतम डीएनए आधारित गणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग 22,446 आंकी गई है। डीएनए आधारित गणना का अर्थ है जानवरों की संख्या का अनुमान उनके आनुवंशिक पदार्थ (जेनेटिक मैटेरियल) के आधार पर लगाना, न कि केवल प्रत्यक्ष रूप से देखकर गिनना। विश्व में हाथियों की दो प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं- अफ्रीकी हाथी जिनकी संख्या लगभग 4-5 लाख है तथा एशियाई हाथी जिनकी संख्या लगभग 50,000-60,000 के बीच है। भारत विश्व के कुल एशियाई हाथियों का 60% से अधिक हिस्सा रखता है।

हाल फिलहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि आज के समय में मानव-हाथी संघर्ष वर्तमान समय की एक गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या बन चुका है। इसका मुख्य कारण वनों का सिकुड़ना, कृषि विस्तार, मानव बस्तियों का बढ़ना और हाथियों के प्राकृतिक मार्गों (कॉरिडोर) का टूटना है। इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष औसतन 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हाथियों के हमलों में होती है। वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 628 तक पहुँच गई, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है। पिछले पाँच वर्षों में 2,800 से अधिक मानव मौतें दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2009-2024 के बीच लगभग 8,000 मानव मौतें हुई हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्य ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ हैं।

दूसरी ओर, हाथियों की मृत्यु भी मानव गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में हो रही है। पिछले 16 वर्षों में 1,653 हाथियों की मौत मानवजनित कारणों से हुई है, जिनमें लगभग 69% मौतें बिजली के करंट से और लगभग 16% रेल दुर्घटनाओं से हुई हैं। पिछले पाँच वर्षों में 528 हाथियों की मौत दर्ज की गई है, जबकि प्रतिवर्ष औसतन 100 से अधिक हाथी मानव-हाथी संघर्ष में मारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अवैध शिकार, जहर देकर मारना तथा पटाखों या जहर मिले फलों से भी हाथियों की मृत्यु के मामले सामने आते रहे हैं। हाल ही में केरल में पटाखों से भरे फल खाने से हाथी की मृत्यु हुई तथा कर्नाटक में किसान की हाथी हमले में मृत्यु की घटना भी दर्ज की गई।

एक गंभीर घटना 20 दिसंबर 2025 को असम के होजाई जिले में हुई, जहाँ सैरंग-नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी तेज गति से गुजर रही थी और लगभग 100 हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। लोको पायलट द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन नहीं रुक सकी और टक्कर हो गई, जिसमें 7 हाथियों की मौके पर तथा एक घायल हाथी की बाद में मृत्यु हो गई, इस प्रकार कुल 8 हाथियों की जान गई। यह घटना उस क्षेत्र में हुई जहाँ हाथियों का प्राकृतिक आवागमन रेलवे ट्रैक के पास से होता है, लेकिन सुरक्षा उपायों और चेतावनी प्रणालियों की कमी के चलते यह हुआ।

इस प्रकार भारत में जहाँ एक ओर मानव जीवन हाथियों के कारण प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हाथी भी मानव गतिविधियों से गंभीर खतरे में हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जंगलों का संरक्षण, हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा, सुरक्षित रेलवे और बिजली व्यवस्था, तकनीकी निगरानी (जैसे जीपीएस ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम) तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, ताकि मानव और वन्यजीव दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण सुरक्षित रह सके।

(लेखक महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।)

नारी शक्ति वंदन: आधी आबादी का हक या 2029 का चुनावी दांव?

यदि महिलाएं सशक्त होती हैं और देश के शासन-प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए इससे बेहतर भला और क्या होगा। आधी आबादी को उनका हक मिलना सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। लेकिन जब हम महिला आरक्षण से जुड़े हालिया घटनाक्रमों और इसके कानूनी पेचीदगियों को देखते हैं, तो साफ नजर आता है कि सरकार की मंशा इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय एक राजनीतिक हथियार के तौर पर अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कानून की सबसे बड़ी और बुनियादी कमी इसका शर्तों में बंधा होना है। सरकार ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन इसके साथ एक ऐसी शर्त जोड़ दी जिसने इसे फिलहाल एक भविष्य का वादा बनाकर छोड़ दिया है। कानून के मुताबिक, आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना होगी और उसके आधार पर सीटों का नया बंटवारा यानी परिसीमन होगा।

दिलीप कुमार पाठक

विशेषज्ञों का मानना है कि इस लंबी प्रक्रिया के कारण यह आरक्षण 2029 या शायद 2034 तक खिंच सकता है। सवाल यह उठता है कि अगर नीयत साफ थी, तो इसे तुरंत मौजूदा सीटों पर ही क्यों लागू नहीं किया गया? जनगणना और परिसीमन जैसी उलझी हुई प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर सरकार ने इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है, जिसकी मंजिल का फिलहाल कोई पता नहीं है। जैसे ही सरकार सीटों के नए बंटवारे की बात करती है, दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता बढ़ जाती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने पिछले कई सालों में जनसंख्या को काबू करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब तकनीकी दिक्कत यह है कि यदि सीटों का फैसला केवल आबादी के आधार पर होता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण का राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सीटें अस्सी प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण में यह बढ़ोतरी बहुत कम होगी। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्हें अच्छा काम करने की सजा दी जा रही है। सरकार ने इस क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने का कोई पक्का रास्ता बताए बिना ही महिला आरक्षण को सीटों के बंटवारे से जोड़ दिया। इससे यह डर पैदा हो गया है कि महिलाओं को हक देने के नाम पर कहीं देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच का तालमेल ही न बिगड़ जाए।

इस बिल की एक और बड़ी व्यावहारिक चिंता प्रॉक्सी संस्कृति और रसूखदार राजनीतिक घरानों का कब्जा है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह नाम महिला का और काम पुरुष का वाली स्थिति है। गाँवों की पंचायतों में हमने अक्सर देखा है कि महिला चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन दफ्तर में उसके पति, पिता या भाई बैठते हैं और सारे फैसले वही लेते हैं। इसे ही पति-सरपंच संस्कृति कहा जाता है। अब डर यह है कि विधानसभा और संसद में भी यही होगा। राजनीतिक पार्टियां जमीन से जुड़ी संघर्षशील महिलाओं के बजाय उन्हीं महिलाओं को टिकट देंगी जो पहले से ताकतवर राजनीतिक परिवारों से आती हैं। यानी एक आम महिला के लिए संसद के दरवाजे अभी भी बंद रह सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो चुका है और महिलाओं के पास अपने खर्च के लिए पैसे नहीं होते। बिना सरकारी मदद या चुनावी खर्च में छूट के, यह आरक्षण केवल अमीर वर्ग की महिलाओं तक सिमट कर रह जाएगा। इसके अलावा, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों को इस आरक्षण से बाहर रखना भी एक बड़ी खामी है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अभी बहुत कम है, फिर भी बड़े सदनों में उनकी भागीदारी पर चुप रहना सरकार की सोच पर सवाल उठाता है। साथ ही, पार्टियों के भीतर लोकतंत्र की कमी एक और कड़वा सच है। जब तक टिकट बांटने वाली मुख्य कमेटियों में महिलाओं को जगह नहीं मिलती, तब तक चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की ताकत केवल कागजों तक ही रहेगी। एक और कमी सीटों के बदलने का नियम है। हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटें बदलने से नेताओं की अपने इलाके के प्रति जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगला चुनाव उन्हें वहां से लड़ना ही नहीं है।

कुल मिलाकर, सरकार ने बिल पास करके सुर्खियां तो बटोर लीं, लेकिन इसे लागू करने में जो रुकावटें छोड़ी हैं, वे इसे एक अधूरा और जल्दबाजी में लिया गया फैसला साबित करती हैं। बिना किसी ठोस तैयारी के, केवल चुनाव की हवा को देखते हुए कानून बना देना लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। जब तक जनगणना, सीटों के बंटवारे और दक्षिण-उत्तर के विवाद का कोई ऐसा हल नहीं निकलता जिससे सब सहमत हों, तब तक यह कानून केवल एक सुनहरा सपना ही रहेगा। असली सशक्तिकरण तब होता जब यह बिना किसी शर्त के और बिना किसी क्षेत्रीय डर के तुरंत लागू किया जाता।

(लेखक पत्रकार हैं)

आंचलिक

पुलिस ने 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' लॉन्च किया

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● खंडवा जिले को नशामुक्त और अपराधमुक्त बनाने के लिए पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ व्यापक और सख्त अभियान शुरू किया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 1 मई से 31 मार्च 2029 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ड्रग्स तस्करी, अवैध नेटवर्क और नशे से अर्जित संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

खंडवा पुलिस ने जिले में नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 'नशे का रोडमैप' तैयार किया है। इसके तहत 31 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 16 शहरी और 15 ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। इन स्थानों पर लगातार निगरानी, दबिश और खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

वन अमले पर हमला, दो महिला समेत 10 पर केस

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● खंडवा जिले के गुड़ी वन परिक्षेत्र में जंगल की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई। सोमवार को भिलाईखेड़ा बीट के आमाखुजरी टांडा में अतिक्रमणकारियों ने जंगल की जमीन पर हल चलाकर खेती की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दौरान वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की तो आरोपियों ने एकजुट होकर वन अमले के साथ झूमाझपटी की और चौकीदार से मारपीट की थी।

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया हैं। वनपाल अंतरसिंह बघेल (44), निवासी गुड़ी वन परिक्षेत्र की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में स्त्रङ्कक दर्ज की है। पुलिस ने रमेश, इंदर सिंह, सुरसिंह, भुवानसिंह, बुचा, गंगाराम, गणपत, सूरज, रामसिंह की पत्नी, गोरेलाल की पत्नी सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 189(2), 132, 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने चौकीदार रामदास को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, गला दबाया और नाखूनों से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही दोबारा कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। वन विभाग के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने हंगामा करते हुए खुद के कपड़े फाड़ लिए, ताकि वन अमले पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि, पूरे घटनाक्रम का वीडियो वन कर्मचारियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में अतिक्रमणकारी बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर जिलों से आकर वन भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अतिक्रमण में मुआसिंह और उसके परिवार के सदस्यों की भूमिका सामने आई है। विभाग के मुताबिक, इनके पट्टे करीब दो महीने पहले निरस्त कर दिए गए थे और बेदखली के आदेश भी जारी हो चुके हैं।

आज खंडवा आएंगे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे ग्राम नेतनगांव और ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को भोपाल के लिए रवाना होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तोमर सुबह 7 बजे गोवा एक्सप्रेस से खंडवा पहुंचेंगे। इसके बाद वे सुबह 10 बजे खंडवा से रवाना होकर 11 बजे पुनासा तहसील के ग्राम नेतनगांव पहुंचेंगे, जहां वे दिवंगत सांसद नंदकुमारसिंह चौहान की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोपहर 1.30 बजे नेतनगांव से प्रस्थान कर वह 2 बजे तीर्थनगरी ओंकारेश्वर पहुंचेंगे, जहां भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद तोमर दोपहर 3.30 बजे ओंकारेश्वर से रवाना होकर शाम 5 बजे खंडवा सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वे शाम 7.20 बजे कर्नाटक एक्सप्रेस से खंडवा से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

सांदीपनी स्कूल में 10वीं का परिणाम निराशाजनक: केवल 26.7% छात्र पास; बोर्ड परीक्षा में विनायक, राधिका-तपस्या रहे ब्लॉक टॉपर

दैनिक इंदौर संकेत

कुक्षी ● मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में धार जिले के बाग और कुक्षी ब्लॉक के विद्यार्थियों ने गौरव बढ़ाया है। बाग के छात्र विनायक राजाराम निंगवाल 12वीं (गणित) में 94.1% अंक लेकर ब्लॉक टॉपर बने। वहीं, कुक्षी की तपस्या सेन ने 10वीं में 95.4% अंक प्राप्त कर ब्लॉक में प्रथम स्थान हासिल किया। बाग के सिटी कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा राधिका अजय प्रजापति ने 10वीं कक्षा में 93% अंक प्राप्त कर ब्लॉक में श्रेष्ठ स्थान पाया है। राधिका के पिता मजदूरी और माता सिलाई का कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इसी स्कूल की प्रियांशी बघेल (92.2%), दुर्गा भाभर (91.2%) और सृष्टि राठौर (90.6%) ने भी 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुक्षी के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा तपस्या आनंदीलाल सेन ने 10वीं में 478 अंक (95.4%) हासिल कर ब्लॉक टॉप किया है। तपस्या के पिता हेयर कटिंग सैलून चलाते हैं। इसके अतिरिक्त बाग के कन्या स्कूल की सबाहत रऊफ खान ने 90% अंक लेकर अपने स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बोर्ड परिणामों में सांदीपनी स्कूल का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। यहां 10वीं कक्षा का सफलता प्रतिशत मात्र 26.7% दर्ज किया गया, जबकि 12वीं में 55% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो सके।

उर्स से लौट रहे परिवार से मारपीट

दैनिक इंदौर संकेत

धामनोद ● धार जिले के धरमपुरी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात बियाबानी उर्स से लौट रहे एक परिवार के साथ मारपीट की गई। ग्राम चंदावड़ चौराहे पर आरोपी ने ओवरटेक के विवाद में कार रोककर हंगामा किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धरमपुरी निवासी रेहान शेख 15 अप्रैल 2026 की रात करीब एक बजे परिवार के साथ बियाबानी मेले से लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम चंदावड़ में मुंडला निवासी राजकुमार मुवेल ने ओवरटेक की बात पर विवाद करते हुए अपनी बाइक कार के सामने खड़ी कर दी। आरोपी ने बीच सड़क पर हंगामा किया, जिससे उर्स से लौट रहे अन्य वाहनों का रास्ता भी बाधित हुआ। विवाद के दौरान आरोपी राजकुमार ने रेहान के साथ मारपीट की, जिसमें कार में सवार महिलाओं को भी चोटें आईं। घटना की सूचना पर जब धरमपुरी थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब भी आरोपी ने दबंगई जारी रखी। मौके पर मौजूद महिलाएं चीखती रहीं, लेकिन आरोपी पुलिस के सामने ही लगातार गाली-गलौज और मारपीट करता रहा।

गर्मी के कारण अब सुबह 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक खुलेंगे स्कूल

दैनिक इंदौर संकेत

बुरहानपुर ● बुरहानपुर में भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने बुधवार शाम आदेश जारी कर सभी स्कूलों का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक निर्धारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिले में पिछले तीन दिनों से अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। पहले स्कूलों का संचालन सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होता था। इससे पहले बुधवार दोपहर को पालक महासंघ ने भी स्कूलों के समय में परिवर्तन की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा था। यह ज्ञापन डीईओ रोहिणी पवार को दिया गया था। जारी आदेश के अनुसार, नवीन शिक्षा सत्र में सभी शासकीय, अशासकीय और सीबीएसई से संबद्ध शालाओं में पहली से लेकर हायर सेकेंडरी तक की कक्षाओं का संचालन नए समय पर होगा।

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मैचों में हुआ बदलाव

मुंबई (एजेंसी) • भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले दो मैचों के कार्यक्रम में बदलाव किया है। गुजरात और सीएसके के बीच 26 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाला मैच अब इसी तारीख को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।

वहीं सीएसकेके और गुजरात के बीच होने वाला दूसरा मैच जो 21 मई, 2026 की शाम को चेन्नई में खेला जाना है। उसे इसी दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरु होगा। दोनों ही मैचों के कार्यक्रम में केवल स्थलों में बदलाव किय गया है। तारीख वहीं रखी गयी है। इस बदलाव का कारण अहमदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनाव हैं।

आईपीएल में अब तक इन दोनो ही टीमों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। दोनो ही टीमों की शुरुआत बहुत ही खराब हुई है। सीएसके को लगातार तीन मैचों में मिली हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहली सफलता मिली. सीएसके के इस सीजन में चार मैचों में सिर्फ 2 अंक हैं। वहीं गुजरात टाइटंस भी खराब दौर से गुजर रही है। अपने डेब्यू सत्र में ही विजेतार रही गुजरात इस बार चार मैचों में सिर्फ 2 में जीत सकी है।

अंक तालिका में आठवें नंबर पर पहुंची सीएसके, केकेआर अंतिम स्थान पर

मुंबई (एजेंसी) • चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच हुए मैच के बाद अंकतालिका में हल्का बदलाव आया है हालांकि शीर्ष सात टीमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सीएसके जीत के साथ ही अब आठवें नंबर पर पहुंच गयी है। वहीं हार के कारया केकेआर अंतिम स्थान पर खिसक गयी है। अंक तालिका में

सीर्ष पर राजस्थान रॉयल्स बनी हुई है। वह पांच मैचों में से चार मैचों में जीत हासिल करने में सफल रही है। रॉयल्स अकेली टीम है जिसके 8 अंक हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स है, जिसने चार में से तीन मैच जीते हैं और एक मैच का परिणाम नहीं आया। पंजाब के 7 अंक हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) चार में से तीन मैच जीतकर 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने पांच में से दो मैच जीते हैं।

पांचवें नंबर पर इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स है, जो 4 में से 2 मैच जीती है। छठे स्थान पर गुजरात टाइटन्स है और सातवें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। दिल्ली, गुजरात और लखनऊ ने 4-4 मैच खेले हैं। 2-2 मैच उनमें से जीते हैं। दो-दो अंक इन टीमों के हैं। वहीं, 8वें स्थान पर अब चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच गई है, जिसे केकेआर के खिलाफ मिली जीत का लाभ हुआ है। वहीं मुंबई इंडियंस 9 वें स्थान पर खिसक गई है।

अंक तालिक

क्रमांक	टीम	मैच	जीत	हार	बेनतीजा	नेट रन रेट	अंक
1	राजस्थान रॉयल्स	5	4	1	0	0.889	8
2	पंजाब किंग्स	4	3	0	1	0.720	7
3	रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु	4	3	1	0	1.148	6
4	सनराइजर्स हैदराबाद	5	2	3	0	0.576	4
5	दिल्ली कैपिटल्स	4	2	2	0	0.322	4
6	गुजरात टाइटन्स	4	2	2	0	-0.029	4
7	लखनऊ सुपर जायंट्स	4	2	2	0	-0.427	4
8	चेन्नई सुपर किंग्स	5	2	3	0	-0.846	4
9	मुंबई इंडियंस	4	1	3	0	-0.772	2
10	कोलकाता नाइट राइडर्स	5	0	4	1	-1.383	1

सामाजिक संदेश के साथ डर का सशक्त मिश्रण है छोरी 2

मुंबई (एजेंसी) • बॉलीवुड एक्टर नुशरत भरुचा अभिनीत छोरी फ्रेंचाइज़ी ने एक अलग पहचान बनाई है। नुशरत भरुचा के शानदार अभिनय से सजी छोरी और छोरी 2 पारंपरिक कहानी कहने के तरीकों से आगे बढ़कर, समाज में व्याप्त गंभीर समस्याओं को इस तरह पेश करती हैं, जो एक साथ दिलचस्प और असहज दोनों लगती हैं।

पहली फिल्म छोरी ने लैंगिक भेदभाव और लड़कों को प्राथमिकता देने जैसी मानसिकता पर प्रकाश डाला था, जिससे वह अपनी मजबूत सामाजिक बात के लिए अलग नजर आई। छोरी 2 ने इस कहानी को और आगे बढ़ाते हुए एक ज्यादा डार्क और जटिल भावनात्मक दायरे में प्रवेश किया, जहाँ डर, मातृत्व और संघर्ष जैसे विषयों को और गहराई से खोजा गया, लेकिन सामाजिक वास्तविकताओं से इसका जुड़ाव बना रहा।

इन फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्होंने सामाजिक मुद्दों को किसी उपदेश की तरह नहीं दिखाया, बल्कि हॉरर के माध्यम से इन प्रथाओं के डर और परिणामों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस फ्रेंचाइज़ी का संतुलन उल्लेखनीय है। हॉरर मौजूद है, लेकिन वह कहानी पर हावी नहीं होता, बल्कि उसे सहारा देता है, जिससे सामाजिक संदेश अधिक प्रभावशाली और सहज तरीके से सामने आता है, न कि उपदेशात्मक ढंग से। यही बात छोरी फ्रेंचाइज़ी को उस जॉनर में अलग बनाती है जहाँ अक्सर कहानी की गहराई पीछे छूट जाती है। नुशरत भरुचा की उपस्थिति दोनों ही फिल्मों में एक निरंतरता और भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती है। उनके किरदार का सफर पूरी कहानी को जोड़ता है, जिससे दर्शक सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि कहानी के अंतर्निहित संदेश में भी विश्वास करते हैं। आज के बदलते कंटेंट माहौल में, जहाँ दर्शक गहराई वाली कहानियों के लिए अधिक खुले हैं, वहाँ छोरी और छोरी 2 बेहद प्रासंगिक महसूस होती हैं। यह दर्शाती हैं कि हॉरर को सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि असहज सच्चाइयों को उजागर करने के एक माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

अभिनेत्री मीना के आलीशान घर के करोडों में बिकने की चर्चा

मुंबई (एजेंसी) • दक्षिण भारतीय की अभिनेत्री मीना के चेन्नई स्थित आलीशान घर को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। अभिनेत्री का यह भव्य घर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये में बिक गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 साल पहले पारंपरिक केरल शैली में महज 10 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए इस घर को अमेरिका के एक एनआरआई कपल ने खरीदा है। हालांकि, अभिनेत्री मीना ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, और उनके सोशल मीडिया पेजों पर भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मीना अपने पति सागर (जिनका निधन हो चुका है) और बेटी नैनिका के साथ इस खूबसूरत घर में रहती थीं। यह घर अपनी अद्वितीय केरल शैली की वास्तुकला, खूबसूरत लकड़ी के खंभों, एक बड़े आंगन, महल जैसे डिजाइन और पारंपरिक तंजावुर की कलाकृतियों के लिए जाना जाता था। मीना की मां राज मल्लिका, जो मूल रूप से कन्नूर की हैं, ने इस घर के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी हर दीवार और कोने में उनकी व्यक्तिगत पसंद और सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती थी। एक्स और कुछ तमिल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घर 100 करोड़ रुपए की भारी कीमत पर उस एनआरआई कपल को बेचा गया है, जो इस प्रॉपर्टी से काफी प्रभावित हुए थे। यह सौदा, यदि पुष्टि होती है, तो चेन्नई के रियल एस्टेट बाजार में एक मील का पत्थर साबित होगा। हालाँकि, मीना या उनके परिवार की ओर से इन खबरों की पुष्टि या खंडन न होने से अभी भी रहस्य बना हुआ है। मीना पहले भी झूठी अफवाहों से अपने परिवार को होने वाली परेशानी के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं। बीते दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, लोग मेरी कथित दूसरी शादी के बारे में चर्चा करते रहते हैं।

उज्जैन संभाग

निगम का सम्मेलन कल, नारी शक्ति वंदन पर चर्चा

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • नगर पालिक निगम का विशेष सम्मिलन 17 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से छत्रपति शिवाजी भवन स्थित नगर निगम के सभागृह में होगा। सम्मिलन की अध्यक्षता निगम अध्यक्ष कलावती यादव करेंगी। बैठक की शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की जाएगी, इसके बाद नारी शक्ति वंदन विषय पर चर्चा प्रस्तावित है।

छात्रावास प्रवेश से पहले प्रोफाइल पंजीयन जरूरी

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • जिले में अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्ग के छात्रावास और आश्रम एमपी टास्क मॉड्यूल से संचालित हो रहे हैं। छात्रावास में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश से पहले प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन के लिए वेबसाइट जाकर हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण किया जा सकता है। एक बार पंजीयन होने के बाद यह हमेशा के लिए हो जाएगा।

महिला कांग्रेस सेवादल की संभागीय बैठक आज

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • मप्र महिला कांग्रेस सेवादल की संभागीय बैठक गुरुवार को सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय क्षीरसागर, उज्जैन में आयोजित होगी। बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल महिला अध्यक्ष संगीता कांकरिया मुख्य अतिथि रहेंगी। बैठक में उज्जैन, शाजापुर और देवास जिलों की महिला कांग्रेस सेवादल की संयुक्त सहभागिता रहेगी। इसमें संगठन को मजबूत करने के लिए कार्ययोजना और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी।

मनरेगा अधिकारी दो दिनों तक सामूहिक अवकाश पर

8 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज अधिकारी काम नहीं करेंगे

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • उज्जैन जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारी, कर्मचारी और उपयंत्री लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर जिले के समस्त तकनीकी अमले और कर्मचारियों ने 16 और 17 अप्रैल को दो दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इससे मनरेगा के कई कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

मनरेगा अभियंता संघ मध्यप्रदेश की ओर से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवगत कराया गया है कि जनपद पंचायतों में कार्यरत उपयंत्रियों को पिछले 8 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार के दैनिक खर्च, बच्चों की स्कूल फीस और इलाज जैसे जरूरी खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया है। लगातार आर्थिक अस्थिरता के चलते कर्मचारियों में मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है।

कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने के बावजूद उन्होंने जलगंगा संवर्धन योजना सहित शासन की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में लगातार काम किया और जिले को बेहतर प्रदर्शन दिलाने में योगदान दिया।

इस आंदोलन में जिले के प्रमुख उपयंत्री और समन्वयक—इंजी. गजेन्द्र कुमार कठाने, इंजी. शेख सिद्दीक कुरैशी, इंजी. सुमित प्रताप सिंह, इंजी. अनिल पांडे, इंजी. विनय जायसवाल, इंजी. कुंदन मुकाती और इंजी. आर.डी. किरार शामिल हैं। वहीं प्रांतीय स्तर पर संघ का नेतृत्व अध्यक्ष इंजी. सतीश समेले, उपाध्यक्ष इंजी. राघवेन्द्र शर्मा और सचिव इंजी. अनुराग राजपूत कर रहे हैं।

संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में सभी संविदा अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिससे मनरेगा के कार्यों पर व्यापक असर पड़ सकता है।

आगर मालवा में हवन के दौरान हादसा, कोई जनहानि नहीं

दैनिक इंदौर संकेत

आगर मालवा • आगर मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर के पास एक निजी यज्ञशाला में हवन के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जानकारी के अनुसार, यज्ञशाला में हवन चल रहा था। इसी दौरान एक यजमान आहुति डाल रहा था कि अचानक अग्नि की लपटें तेज हो गईं। इन लपटों की चपेट में आने से यजमान की धोती में आग लग गई। हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और यजमान बाल-बाल बच गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यजमान की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास पंडितों ने एक निजी हवन कुंड बनाकर यह यज्ञशाला संचालित कर रखी है, जहाँ नियमित रूप से हवन किए जाते हैं। इस घटना के बाद यज्ञशाला में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

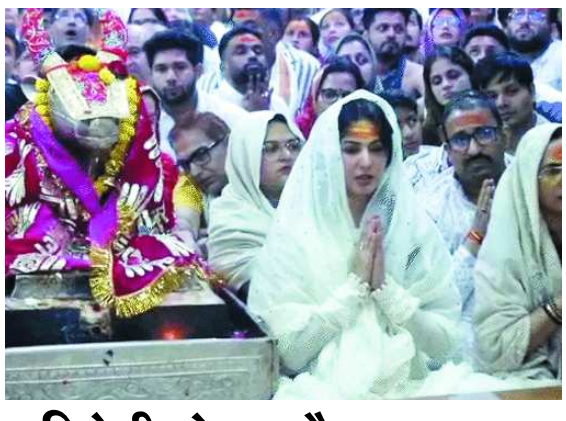

अभिनेत्री सोनल चौहान महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचीं

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • हिंदी और तेलगु फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री और मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब जीतने वाली सोनल चौहान गुरुवार को महाकाल मंदिर पहुंचीं। उन्होंने तड़के चार बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सोनल चौहान, ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए रात करीब दो बजे महाकाल मंदिर पहुंचीं। इस दौरान करीब दो घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में शामिल हुईं। सोनल ने नंदी जी का पूजन कर कान में अपनी मनोकामना कही। आरती के दौरान भगवान महाकाल का जाप करते हुए नजर आईं सोनल ने आरती के बाद भगवान महाकाल की देहरी से दर्शन कर जल अर्पित कर भगवान का आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर समिति की ओर से सोनल का सम्मान किया गया। सोनल चौहान ने कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है। वे 2005 में फेमिना मिस इंडिया और 2005 में मिस वर्ल्ड टूरिज्म की विजेता भी रही हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म जन्नत और तेलुगु फिल्म रेनबो से अपने अभिनय से करियर की शुरुआत की थी।

सीएमओ ने मोती सागर तालाब से जलकुंभी हटाई

दैनिक इंदौर संकेत

आगर मालवा • आगर मालवा में नगर पालिका परिषद ने 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत बुधवार दोपहर मोती सागर तालाब पर सफाई अभियान चलाया। इसका उद्देश्य तालाब को साफ रखना, पानी बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। अभियान के दौरान तालाब से जलकुंभी, प्लास्टिक और अन्य कचरा निकाला गया। नगर पालिका की टीम ने कचरे को सही तरीके से हटाकर निस्तारित किया। सफाई के बाद तालाब का पानी साफ नजर आने लगा और आसपास का इलाका भी बेहतर दिखने लगा। इस अभियान में सीएमओ कुशल सिंह डोडवे, विधायक प्रतिनिधि अशोक प्रजापत, उपयंत्री निधि पटेल, स्वच्छता निरीक्षक बसंत दुलगंज और नगर पालिका की टीम शामिल रही। एसके वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस के सदस्यों ने भी सहयोग किया। नगर पालिका ने बताया कि शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्षों की ली क्लास

राष्ट्रीय पदाधिकारी ने किया वन-टू-वन; जीतू पटवारी बोले- काम करने वाले ही पद पर रहेंगे

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को दिन भर मैराथन बैठकें और ट्रेनिंग चली। दो चरणों में विधानसभा प्रभारियों को जॉब रिस्पांसिबिलिटी और आगे किए जाने वाले काम की जानकारी दी गई। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी चेल्ला वामसी रेड्?डी ने उज्जैन और इंदौर संभाग के जिला अध्यक्षों से वन-टू-वन मीटिंग कर अब तक किए गए कामों की समीक्षा की।

बैठक में जिला अध्यक्षों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, जिसमें पिछले छह महीनों के प्रदर्शन का मूल्यांकन तय मापदंडों पर किया गया। 'कनेक्ट सेंटर' के जरिए पदाधिकारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। संगठन अब डिजिटल ट्रैकिंग मोड में आ गया है। कनेक्ट सेंटर के जरिए दिए गए काम और उनके क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है। जिलाध्यक्षों से हुई वन-टू-वन मीटिंग में वामसी रेड्?डी ने पूछा कि ब्लॉक कमेटी से लेकर वार्ड और पंचायत कांग्रेस कमेटियों के गठन का काम कितना पूरा हुआ है? जिन जिलों में काम नहीं हो पाया उसकी वजह पूछी। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर किए गए आंदोलन-प्रदर्शन की जानकारी भी ली गई।

पटवारी बोले- पद से नहीं काम से होगी प्रोग्रेस-प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया कि पार्टी में अब केवल

पद होना पर्याप्त नहीं होगा। काम नहीं करने वालों की जिम्मेदारी भी तय होगी। विधानसभा प्रभारियों की बैठक में जीतू पटवारी ने 230 प्रभारियों को 'रीढ़ की हड्डी' बताते हुए उन्हें सीधे गांव-गांव जाकर संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें पंचायत स्तर तक कांग्रेस कमेटियों का सत्यापन, नियमित बैठकें और 'सृजन संवाद' जैसे कार्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में हरीश चौधरी, कमलेश्वर पटेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी साफ किया कि आने वाले समय में जमीनी सक्रियता ही काम की मॉनिटरिंग का मुख्य पैमाना होगी।

एमआईसी मेंबर की आपत्ति पर कार्रवाई तो नहीं हुई, उल्टा लग गई विज्ञापन स्क्रीन

मेट्रो ट्रैक के नीचे डिवाइडर पर लगे विज्ञापन पर उठाए थे सवाल

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर द्वारा आपत्ति दर्ज कराने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बावजूद रेडिसन चौराहे के पास मेट्रो ट्रैक कॉरिडोर के नीचे डिवाइडर पर एलईडी विज्ञापन स्क्रीन लगा दी गई है। राठौर ने आरोप लगाया था कि बिना टेंडर और उचित प्रक्रिया के अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, जबकि नगर निगम की ओर से इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने और जांच की मांग भी की थी। वे स्वयं मौके पर पहुंचे और मामले को उजागर किया, लेकिन कुछ ही दिनों में मामला ठंडा पड़ गया।

अब एलईडी स्क्रीन से बढ़ा हादसों का खतरा-रेडिसन चौराहे से विजयनगर की ओर जहां पहले ग्लॉसाइन (लालीपॉप) बोर्ड लगाए जा रहे थे, अब वहां एलईडी स्क्रीन लगा दी गई है। यह क्षेत्र तेज रफ्तार यातायात वाला है, जहां सिग्नल ग्रीन होने के बाद वाहन तेजी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में स्क्रीन पर चल रहे विज्ञापन से वाहन चालकों का ध्यान भटक सकता है, जिससे पीछे से टक्कर और सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है।

यातायात नियमों का उल्लंघन-डिवाइडर पर चौराहे से 50 मीटर की दूरी पर स्क्रीन लगाना यातायात नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। इस लापरवाही को लेकर यातायात पुलिस को पत्र लिखकर अवगत कराने की बात कही गई है। पश्चिम क्षेत्र के यातायात एसीपी लालबहादुर बौद्ध ने कहा कि स्क्रीन सामान्यत: वहीं लगाई जानी चाहिए जहां ट्रैफिक रुकता है, जैसे चौराहे। चलते हुए ट्रैफिक में इसे लगाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वाहन चालकों का ध्यान भटकता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। अधिक रोशनी भी वाहन संतुलन बिगाड़ सकती है। मामले में निरीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी।

महापौर के निर्देश भी बेअसर-एमआईसी मेंबर राठौर के अनुसार शहर में विज्ञापन अधिकार अलग-अलग एजेंसियों (स्मार्ट सिटी, एआईसीटीएसएल और एसबीएम) को दिए गए हैं, जिसके कारण समन्वय की कमी है और एजेंसियां मनमानी कर रही हैं। उन्होंने एकीकृत एजेंसी बनाने की आवश्यकता बताई। राठौर ने बताया कि उन्होंने यह मामला महापौर पुष्यमित्र भार्गव के संज्ञान में भी लाया था। महापौर ने जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक संबंधित एजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी महापौर के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं।

ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के 2 करोड़ के डामर घोटाले की शुरू की जांच, चिंटू ने खोला 12 लाख का सड़क घोटाला

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● नगर निगम में 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले की आंच थमी नहीं कि अब नए घोटाले की जांच शुरू हो गई है। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने ईओडब्ल्यू पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन और एसपी रामेश्वर यादव को डामर घोटाले को लेकर शिकायत की थी। इसमें कई अधिकारियों के नाम थे। इसकी जांच शुरू हो गई है। इसमें शिकायतकर्ता को अब 22 अप्रैल को सभी दस्तावेज के साथ बयान के लिए बुलाया गया है।

इन सभी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत-यह शिकायत इंदौर में अपर आयुक्त देवधर दरवाई, अभय राजनगांवकर के साथ अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी,

तत्कालीन कार्यपालन यंत्री असित खरे, सहायक यंत्री सत्येंद्र राजपूत, उपयंत्री उद्देश्य तिवारी, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक प्रशांत दिघे, मेसर्स एप्रेन टेस्ट लेब्स, राजेंद्र कुमार मंत्री व बिल भुगतान को मंजूर करने वाले के खिलाफ है।

यह है मामला-कौशल और रवि गुरनानी ने बताया कि निगम द्वारा शहर की सड़कों के पेंचवर्क काम के लिए पांच हिस्सों में बांटकर पैकेज तैयार हुए। यह 15 करोड़ के थे। लेकिन ठेका देने में पीडब्ल्यूडी के नियमों को ताक पर रखा गया। ठेकेदार ने घटिया डामर का उपयोग किया और सड़कें उखड़ गईं। इसके बाद भी ठेकेदार को दो करोड़ का भुगतान किया गया। यह खुला भ्रष्टाचार था और इसके चलते टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया।

चिंटू चौकसे ने 12 लाख के घोटाले के आरोप लगाए-उधर, निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सड़क घोटाले के आरोप लगाए। चिंटू ने कहा कि एक रोड को बिना बनाए ही उसका 12 लाख का भुगतान ठेकेदार को हो गया। साथ ही अब दोबारा टेंडर लगा दिया गया है, वह भी 22 लाख का। चिंटू ने इसकी शिकायत लोकायुक्त को करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि यादवनंद नगर गली नंबर दो रोड वार्ड 12 जोन 4 की प्रेम परमार गली में सीसी रोड के लिए 13.54 लाख का टेंडर हुआ, लेकिन वहां मौके पर काम ही नहीं हुआ। इसके बाद भी बिल भुगतान हो गया। चिंटू ने निगम को भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बताया।

खजराना के पुजारी पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज

दूसरी पत्नी महिला थाने पहुंची, 1 करोड़-फॉर्च्यूनर के लिए प्रताड़ना के आरोप

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● खजराना गणेश मंदिर से जुड़े पुजारी पुनीत भट्ट के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला का कहना है कि आरोपी पति और ससुराल पक्ष द्वारा 1 करोड़ रुपए नकद और फॉर्च्यूनर कार की मांग की जा रही थी। महिला थाना टीआई श्रद्धा यादव ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मामले की जांच की गई। सभी पक्षों के बयान लिये गए। इसके बाद केस दर्ज किया है। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले जनसुनवाई में आवेदन लेकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। जांच के बाद पुजारी पुनीत भट्ट के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले करीब 22 दिन पहले पीड़िता इंदिरा भट्ट ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में जनसुनवाई में भी शिकायत दी थी। इसमें पति पुनीत भट्ट सहित सास, ननद, नंदोई और देवरों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। महिला ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और घर से निकालने की बात कही थी। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 17 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। यह दोनों की दूसरी शादी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जुलाई 2025 के बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया। इसके बाद लगातार दहेज के लिए दबाव बनाया जाने लगा। महिला का आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष ने मायके से 1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर कार लाने की मांग की।

रोबोट चौराहे पर एसआई-ट्रेवल्स संचालक भिड़े

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● खजराना इलाके स्थित रोबोट चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान एसआई और बस एजेंसी संचालक के बीच विवाद हो गया। बस खड़ी कर सवारी भरने को लेकर शुरू हुई बहस ने तूल पकड़ लिया।

एजेंसी संचालक ने एसआई पर पैसे मांगने का आरोप लगाया, जबकि एसआई ने उल्टा उन पर अभद्रता और धक्का-मुक्की का आरोप लगाया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एसआई सुरेंद्र सिंह ने शिवानी ट्रेवल्स की बस को रोबोट चौराहे पर सवारी भरते समय रोका। इसी बात को लेकर एजेंसी संचालक सुनील चौहान (निवासी मेघदूत नगर) से उनकी बहस हो गई। मौके पर सुनील का भतीजा यशराज भी मौजूद था। देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और आसपास लोग इकट्ठा हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि एसआई सुरेंद्र सिंह ही पहले धक्का-मुक्की करते नजर आए। वहीं एसआई ने आरोप लगाया कि सुनील चौहान ने भीड़ के साथ मिलकर कॉलर पकड़ ली। इस दौरान एसआई ने खुद भी मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और लोगों को चेतावनी देते दिखे। विवाद बढ़ने पर एसआई ने खजराना थाने पर सूचना दी और डायल-112 बुलाया। इसके बाद सुनील चौहान और उनके भतीजे को जबरन थाने ले जाया गया। देर रात पुलिस ने एसआई की शिकायत पर दोनों को थाने में बैठा लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उसी स्थान पर अन्य ट्रेवल्स की बसें भी रुकती हैं, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती।

बिजली कार्मिकों की क्षमता वृद्धि की ट्रेनिंग

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में केएफडबल्यू परियोजना अंतर्गत ट्रांसफार्मर, ग्रिडों के कार्य होंगे। केएफडब्ल्यू परियोजना के बेहतर संचालन के लिए पोलोग्राउंड स्थित सभागार में बुधवार को विद्युत सुधार कार्यक्रम एवं क्षमता वृद्धि विषय को लेकर कार्मिकों की ट्रेनिंग आयोजित हुई। इस अवसर पर कंपनी के मुख्य अभियंता कार्य श्री एसएल करवाड़िया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एससी वर्मा, संयुक्त सचिव श्री तरूण उपाध्याय प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

राज मोहल्ला बिजली ग्रिड का निरीक्षण- मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री आरके आर्य ने बुधवार दोपहर इंदौर शहर वृत्त अंतर्गत राज मोहल्ला 33/11 केवी सब स्टेशन का निरीक्षण कर गुणात्मक सुधार के निर्देश दिए।

शहर में जनप्रतिनिधि वंदे मातरम् में व्यस्त, जनता समस्याओं से त्रस्त

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का आंकड़ा पहुंचा 3,900 के पार

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में जनप्रतिनिधियों की व्यस्तता और प्रशासनिक सुस्ती के बीच शहर की आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। पार्षदों से लेकर अधिकारियों तक कहीं सुनवाई नहीं होने के चलते लोगों ने अब सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जहां शिकायतों का आंकड़ा 3,900 तक पहुंच गया है। ये हालात साफ इशारा करते हैं कि नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच समन्वय पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है।

चौंकाने वाली बात यह है कि जिस

भागीरथपुरा कांड ने इंदौर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल की थी, उसी से जुड़े विभाग की शिकायतें भी 1200 के पार जा चुकी हैं। ये शिकायतें सीएम हेल्पलाइन ऐप और महापौर हेल्पलाइन पर दर्ज की जा रही हैं। भागीरथपुरा कांड के बाद लोग अभी भी गंदे पानी की शिकायतें कर रहे हैं।

इसके अलावा शहर में पानी नहीं मिलने, बोरिंग में पानी कम होने, टैंकरों से पानी नहीं मिलने और और जगह-जगह अतिक्रमण होने से संबंधित शिकायतें हैं। पानी की शिकायतें तेजी से बढ़ती हैं और सभी 85 वार्डों में नागरिक पानी के लिए परेशान होते हैं। सीएम हेल्पलाइन में कुल शिकायतें जहां 3900 हैं, वहीं लेवल-1 में 2246 शिकायतें दर्ज हैं, जिन्हें जोन के अधिकारी देखते हैं। मगर लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जोनल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सीएसआई और इंजीनियर शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए, मगर अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अब वेतन काटने के साथ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, जिससे अधिकारियों-कर्मचारियों को सबक मिल सके। इसी तरह मेयर हेल्पलाइन ऐप में भी शिकायतें दर्ज होती हैं, जिन्हें 24 घंटे में हल करना होता है।

अपने रिजल्ट से नहीं हैं संतुष्ट? री-चेकिंग के लिए करें अप्लाई

मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं कक्षा के बहुप्रतीक्षित परिणाम जारी कर दिए हैं। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है और वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने नतीजे देख सकते हैं। इस वर्ष की परीक्षा में, प्रतिभा सिंह सोलंकी ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में टॉप कर प्रथम स्थान हासिल किया है। जहां एक ओर कई छात्र अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपने प्राप्त अंकों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे छात्रों के लिए MPBSE ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का विकल्प उपलब्ध कराया है। यह प्रक्रिया छात्रों को अपने परिणामों की समीक्षा करवाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शन के प्रति अधिक स्पष्टता मिल सके।

प्रतिभा सिंह सोलंकी ने किया टॉप-*एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 में प्रतिभा सिंह सोलंकी ने पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 500 में से 499 अंक लाकर पुरे प्रदेश में टॉप किया है। उनकी इस सफलता ने न केवल उनके परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि प्रदेश के अन्य छात्रों को भी कड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।*

री-टोटलिंग और पुनर्मूल्यांकन क्या है?

परिणाम जारी होने के बाद, कई बार छात्रों को लगता है कि उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ है या अंकों के जोड़ में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसी स्थिति में दो मुख्य विकल्प उपलब्ध होते हैं:

री-टोटलिंग (पुनर्गणना): *इस प्रक्रिया में केवल यह जांच की जाती है कि छात्र द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग सही किया गया है या नहीं। इसमें किसी प्रश्न के उत्तर का दोबारा मूल्यांकन नहीं किया जाता।*

पुनर्मूल्यांकन (री-चेकिंग): *यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें उत्तर पुस्तिका का पुन: मूल्यांकन किया जाता है। इसमें यह जांच की जाती है कि सभी प्रश्नों की जांच हुई है या नहीं, और यदि कोई प्रश्न बिना जांचा रह गया है, तो उसे जाँचा जाता है। हालांकि, इसमें पूरे पेपर का दोबारा मूल्यांकन नए सिरे से नहीं किया जाता, बल्कि गलतियों को सुधारा जाता है।*

पुनर्मूल्यांकन और री-टोटलिंग के लिए आवेदन कैसे करें?

जो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना होगा: सबसे पहले, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर 'एमपी बोर्ड 10वीं री-टोटलिंग/पुनर्मूल्यांकन 2026' या संबंधित लिंक खोजें। लिंक पर क्लिक करने के बाद, एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनी रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। अपनी पसंद के अनुसार री-टोटलिंग या पुनर्मूल्यांकन का विकल्प चुनें। आप एक या अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। शुल्क प्रति विषय के हिसाब से तय किया जाता है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद का प्रिंटआउट लेना न भूलें।

महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क-*पुनर्मूल्यांकन और री-टोटलिंग के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द ही MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण तिथि से चूक न जाएं। आवेदन शुल्क भी वेबसाइट पर विस्तार से बताया जाएगा, जो आमतौर पर प्रति विषय के हिसाब से निर्धारित होता है। यह प्रक्रिया उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जिन्हें लगता है कि उनके वास्तविक प्रदर्शन को उनके अंकों में ठीक से दर्शाया नहीं गया है। बोर्ड का यह कदम छात्रों के प्रति पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।*

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।